ईश्वरचन्द विद्यासागर से भाजपा को नफ़रत क्यों ?

पेरियार, अम्बेडकर, लेनिन की मूर्ति तोड़ने के बाद बीजेपी की इस मुहिम का अगला निशाना श्री ईश्वरचन्द्र विद्यासागर जी बने हैं। मंगलवार 14 मई 2019 को बीजेपी के गुण्डों ने कलकत्ता के ईश्वरचन्द्र विद्यासागर महाविद्यालय में स्थापित उनकी मूर्ति को तोड़ दिया। आइये पहले इस महान समाज सुधारक ईश्वरचन्द्र जी के बारे में जान लें ताकि ये समझ सकें कि बीजेपी को आखिर वो इतने क्यों अखरे कि उनकी मूर्ति उन्होंने कॉलेज में घुसकर तोड़ दी।

ईश्वरचन्द्र जी का पूरा नाम ईश्वरचन्द्र बन्दोपाध्याय था। बाद में शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान के कारण उनका नाम ईश्वरचन्द्र विद्यासागर पड़ गया। उन्होंने संस्कृत में विद्या ग्रहण की और 25 साल की उम्र में उनको संस्कृत महाविद्यालय में अध्यापक नियुक्त किया गया जहां उन्होंने तीन साल नौकरी की। इस महाविद्यालय में सिर्फ़ ब्राह्मणों के बच्चे ही दाखिला ले सकते थे। लड़कियों के पढ़ने की भी मनाही थी। यह 1846 की बात है। तीन साल बाद इस कॉलेज के ब्राह्मणवाद के विरोध में यह नौकरी छोड़ दी। बाद में इसी कॉलेज में वह प्राचार्य बनकर आये और इस कॉलेज के द्वार उन्होंने हर जाति के लड़के व लड़कियों के लिये खोल दिये। बाद में इसी कॉलेज का नाम बदलकर उनके नाम पर विद्यासागर कॉलेज कर दिया गया।

उन्होंने अंग्रेजों से मिलकर विधवा विवाह के लिये कानून बनवाया जिसका ब्राह्मणों ने खूब विरोध किया। उन्होंने स्वयं अपने इकलौते पुत्र का विवाह एक बालपन में विधवा हो गयी युवती से किया। उन्होंने जगह-जगह लड़कियों की शिक्षा के लिये स्कूल खोले। उन्होंने सती प्रथा का भी विरोध किया।

बंगाली भाषा की लिपि की वर्णमाला को ज्यादा वैज्ञानिक बनाने के लिये उन्होंने उसमें सुधार किये और इस पर एक पुस्तक लिखी जिसका नाम ''वर्ण परिचय'' था। यह पुस्तक बंगाल में आज भी पढाई जाती है। उन्होंने अंग्रेज सरकार द्वारा संस्कृत पाठशालाओं और फ़ारसी मदरसों को वित्तीय सहायता दिये जाने का विरोध किया और इनमें विज्ञान विषयों को पढाये जाने पर जोर दिया।

स्पष्ट है कि विद्यासागर जी ने अपना सारा जीवन सभी लोग़ों के लिये सस्ती और वैज्ञानिक शिक्षा उपलब्ध कराने व उनको ब्राह्मणवाद की जकड़न से मुक्त करने में लगाया। इसीलिये वे पूरे बंगाल में ब्राह्मण विरोध को झेलते रहे लेकिन आम जन में वे बेहद लोकप्रिय हो गये। उनके इन ब्राह्मणवाद विरोधी काम ही के कारण वे आज भाजपा को शत्रु लगते हैं और उनके निशाने पर हैं।

ब्राह्मणवाद और सवर्ण जातियों की राजनीति करने वाली भाजपा ने एक षडयन्त्र के तहत विद्यासागर कॉलेज पर हमला किया और वहां स्थापित उनकी प्रतिमा को तोड़ा। ये सब कुछ एक पूर्व नियोजित साजिश के तहत किया गया। इस बारे में गौर करने लायक है कि घटना 5.30 बजे सांय के बाद की है जब कॉलेज में छुट्टी हो चुकी थी और कॉलेज के कर्मचारी मोहंती ने रोड शो पर खुलने वाले कॉलेज के गेट पर ताला लगा दिया था। इसके आगे कॉलेज के अंदर वाले गेट पर भी ताला लगा था। उस समय कॉलेज में बहुत ही कम छात्र मौजूद थे। ऐसे में कितने कम छात्र अमितशाह की गुंडा रैली पर पत्थर फेकेंगे ये बात गले उतरना मुश्किल है। ये भी विभिन्न वीडियों में सिद्ध हो चुका है कि बीजेपी के गुंडों ने कॉलेज के दोनों गेटों के तालों को तोड़कर अंदर आकर विद्यासागर जी की प्रतिमा को तोड़ा। कॉलेज के प्रिंसिपल ने भी इस बात की पुष्टि एक बयान में की है

इन सबसे स्पष्ट है कि विद्यासागर कॉलेज पर हमला सोच-समझकर, योजना बनाकर किया गया। और ऐसी योजना अमितशाह जैसा शातिर अपराधी ही बना सकता था जिसे 2002 के गुजरात मुस्लिम कत्लेआम करने का अनुभव था। आखिर क्यों ? इससे बीजेपी ने एक तीर से दो निशाने साधे हैं। एक तो विद्यासागर जी की प्रतिमा तोड़कर सवर्णों की उनके प्रति जो नफ़रत थी उसको हवा दी है ताकि वो गोलबन्द होकर बीजेपी को वोट दें और दूसरी तरफ़ ऐसे प्रतिष्ठित कॉलेज में हुई हिंसा सभी अखबारों में प्रमुख स्थान पा गई। जिसका फ़ायदा उठाकर ना सिर्फ़ ममता को बदनाम किया गया बल्कि ऐसे अफसरों को चुनाव आयोग से कहकर हटवा दिया गया जो बीजेपी के इशारों पर नाचने को तैयार नहीं थे, जो बीजेपी को चुनाव में धांधली नहीं करने दे रहे थे। वरना एडीजी (सीआईडी) व गृह सचिव का क्या रोल था, क्या कमी थी जो उनको हटाया गया। इस बारे में पुलिस और सरकारी मशीनरी ने पूरी मुस्तैदी से काम किया, कोई कोताही नहीं बरती। बीस मिनट में सब कुछ काबू कर लिया गया। फ़िर भी उनको जिम्मेदार ठहराना! क्या वो उन अफ़सरों से भी निकम्में थे जो 2002 में पूरे तीन दिन गुजरात को जलता हुआ देखते रहे, और वो जो पूरे दो दिन 2016 में हरियाणा को जलता देखते रहे और हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहे। और दूसरी तरफ़ 14 मई की घटना पर चुनाव आयोग ने दूसरी कार्रवाई की चुनाव प्रचार एक दिन पहले यानी 16 मई की रात 10 बजे बन्द करने की। क्योंकि 16 मई को दिन में वहां मोदी जी की रैली थी जिसको रोकने की आयोग की औकात नहीं थी। अगर 14 की हिंसा से इतना ही चुनाव प्रभावित था तो 15 मई को ही चुनाव प्रचार क्यों नहीं बन्द कर दिया गया, 16 तक का समय देने की जरूरत क्या थी। क्या चुनाव आयोग के पास इससे ज्यादा नंगा होने को कुछ बचा है।

साइबर नजर

दोगलापन

साध्वी प्रज्ञा भगवा बाने में चुनाव लड़ सकती है और चुनाव आयोग के प्रतिबन्ध के बावजूद मन्दिर में जाने के बहाने चुनाव-प्रचार कर सकती है। योगी आदित्यनाथ मठाधीश होते हुये मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं यानी धर्म निरपेक्ष राष्ट्र होते हुए भी धर्म और राजनीति की मिलावट कर सकते हैं।

अमितशाह अपनी रैली में सैंकड़ों लोग़ों को हनुमान, राम और शिवजी के वेश में घुमा सकते हैं और जय श्री राम के नारे लगाकर ममता दीदी को चुनौती दे सकते हैं कि लो हमने अपने चुनाव-प्रचार में धर्म का इस्तेमाल कर लिया, उखाड़ लो तुम क्या उखाड़ोगे । लेकिन एफ़आईआर दर्ज़ होगी दिग्विजय के खिलाफ़ कि उन्होंने कम्प्यूटर बाबा से हवन यज्ञ क्यों करवाया । ये भाजपाई बाबे क्या तुम्हारे रिश्तेदार लगते हैं चुनाव आयोग जो इन पर कार्रवाई नहीं करते ? शायद लोग ये भी नहीं भूले होंगे कि कर्नाटक चुनाव के वक्त चुनाव-प्रचार थमते ही चौकीदार ने कैसे जाकर नेपाल में पशुपतिनाथ मन्दिर में मत्था टेका था और उसका पूरा प्रचार रेडियो और टीवी पर करवाया था। तब भी चुनाव आयोग को कहीं से आचार संहिता टूटती नज़र नहीं आयी। आचार संहिता भी कहीं-कहीं बहुत मजबूत है, पार्टी देखकर टूटती है।

अजातशत्रु

गुलाम आयोग

14 मई 2019 को अमितशाह ने अपने गुन्डों के साथ लोग़ों को डराने के लिये रैली निकाली। यूपी, मध्य प्रदेश, गुजरात आदि से लाये हुये हज़ारों भाड़े के गुंडे, लाठी डण्डों सहित कलकत्ता की सड़कों पर उतरे- अमितशाह की अगुवाई में। लोग़ों को डराने में कोई कमी न रह जाये इसलिये इन्होंने रास्ते में पड़ने वाले विद्यासागर कॉलेज में तोड़-फ़ोड़ की व समाज सुधारक ईश्वरचंद विद्यासागर की प्रतिमा को भी तोड़ दिया। अगर पुलिस तुरन्त पहुंच कर कार्यवाही न करती तो अमित शाह की गुंडा वाहिनी और उत्पात मचाती। 15 मई को गुणा भाग कर के चुनाव आयोग ने अभूतपूर्व कदम उठाते हुये 16 मई को यानी ठीक एक दिन का वक्त (हिंसा के लिये ?) और देते हुये, रात 10 बजे चुनाव-प्रचार बन्द करने के आदेश दिये। क्यों चुनाव आयोग जी अगर हिंसा इतनी जबरदस्त थी तो एक दिन का वक्त क्यों और गंवाया। क्या उस दिन मोदी की रैली थी इसलिये ? क्या चुनाव आयोग में मोदी/ बीजेपी के खिलाफ़ और सच्चाई के पक्ष में खड़ा होने की हिम्मत नहीं है।

चुनाव आयेग ने तो मोदी की गुलामी स्वीकार कर ली अब बंगाल की जनता को तय करना है कि वो मोदी और मोटू की गुण्डागर्दी से डरकर उनकी अधीनता स्वीकारेगी या उनको करारा जवाब देगी।

-अजातशत्रु

अवतार का प्रबन्धन कमज़ोर, जम कर हुई धांधली, पराजय निश्चित

फ़रीदाबाद (म.मो.) जितनी उछल-कूद व धूम-धड़ाके के साथ अवतार भड़ाना चुनाव में कुदे थे, उसके मुकाबले उनका चुनाव अभियान एवं बूथ-प्रबंधन टांय-टांय फ़िस्स ही कहा जा सकता है। शायद ही किसी बूथ पर इनका कोई पोलिंग एजेंट तैनात रहा हो। इस संवाददाता ने दर्जनों बूथों से जो रिपोर्ट ली उनमें भाजपा के ही पोलिंग एजेंट मौजूद थे। पोलिंग शुरू होने से एक घंटा पूर्व पोलिंग अधिकारी मॉक पोलिंग यानी मशीनों की टेस्टिंग के लिये पोलिंग करते हैं जो पोलिंग एजेंटों के सामने होनी चाहिये। इसके लिये अधिकारी 20 मिनट तक इंतज़ार भी करते हैं। लेकिन जब 6.20 तक भी, भाजपा के अलावा किसी के भी एजेंट नहीं पहुंचे तो मॉक पोलिंग शुरू कर दी गयी। इस मॉक पोलिंग में 50 वोट डाले जाते हैं। मशीन एवं पूरे सिस्टम को दुरुस्त पाये जाने के बाद उन 50 वोटों को मशीन से निकाल कर यानी खाली करके एजेंटों के सामने सीलबंद कर दिया जाता है। जब किसी अन्य पार्टी का कोई एजेंट ही इस अवसर पर मौजूद ही न हो तो सत्तारूढ़ दल (भाजपा) का एजेंट एवं पोलिंग अधिकारी मिल कर कुछ भी कर सकते हैं।

भाजपा के पोलिंग एजेंट गिर्राज सिंह ने असावटी में जिस तरह से अपनी पार्टी के पक्ष में मतदान कराया, क्या यही सब अन्य मतदान केन्द्रो पर नहीं हुआ होगा? गिर्राज सिंह अपने बचाव में साफ़ कहता है कि यदि वह कुछ ग़लत कर रहा था तो दूसरे किसी एजेंट ने उसे रोका-टोका क्यों नहीं? रोकता-टोकता कौन, जब वहां भाजपा के अलावा अन्य कोई पोलिंग एजेंट मौजूद ही नहीं था? यह तो किसी तरह इस सारे कांड का वीडियो वायरल हो गया, एनडीटीवी चैनल वाले वहां पहुंच गये और पूरे निर्वाचन आयोग एवं उनकी व्यवस्था पर सवाल उठने लगे तो कहीं जाकर दो बूथों पर मतदान रद्द करके पुनर्मतदान के आदेश देने पड़े। लेकिन जहां अधिकांश बूथों पर यही खेल खेला गया हो, वहां दो बूथों पर पुनर्मतदान से क्या होने वाला है ?

अनपढ अवतार की अब तक की राजनीति केवल और केवल पैसे के बल पर चलती आई है। इसी पैसे के दम पर वे अच्छे सलाहकार, चुनाव प्रबन्धक, प्रचार प्रबंधक आदि को अपने साथ जोड़ने में सफ़ल होते रहे हैं। परन्तु इस बार उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। उनके निकट रहने वालों का कहना है कि इस बार का प्रबन्धन एवं खर्च पर उनकी पत्नी ममता का सीधा नियन्त्रण था। कंजूसी के चलते इस बार यही प्रबन्धन ठीक से नहीं हो पाया, बाकी कोई योग्यता तो अवतार के पास न पहले कभी थी और न आज।

दूसरी ओर कृष्णपाल के पास आरएसएस व भाजपा का मजबूत संगठन व बीते 5 साल में लूटा अथाह धन बल जो था, उसका उन्होंने जमकर बड़ी होशियारी से इस्तेमाल किया। यदि कृष्णपाल यह चुनाव जीतते हैं तो इसका अर्थ यह निकलेगा कि जनता को न तो मंझावली यमुना पुल की जरूरत है न चौथी रेलवे लाइन और रेलवे स्टेशन की। इससे यह भी संदेश मिलेगा कि अगली बार कृष्णपाल को किसी प्रकार का कोई काम करने की जरूरत नहीं, जितना लूटा जा सके उतना लूट लिया जाय। चुनाव के वक्त भारत माता की जय व जय श्री राम के नारों के साथ मोदी जी एक-दो सर्जिकल स्ट्राइक करा दें तो इस जनता के लिये काफ़ी रहेगा।

डीसी अतुल की विदाई, अंध-भक्ति भी काम न आई

फ़रीदाबाद (म.मो.) रविवार, 12 मई को लोकसभा के लिये मतदान प्रक्रिया पूरी होते-होते डीसी अतुल द्विवेदी जो कि इस चुनाव के मुख्य अधिकारी भी थे, का तबादला हो गया।

सरकारी नौकरी में किसी अधिकारी का तबादला होना कोई बड़ी अथवा अपमानजनक बात नहीं होती; परंतु जिस ढंग से रातों-रात उनको पद से हटा कर सोमवार की सुबह नये उपायुक्त को तैनात कर दिया गया, इतना ही नहीं अतुल को कोई नई पोस्टिंग भी नहीं दी गयी, यह वास्तव में अपमानजनक है।

आमतौर पर चुनाव प्रक्रिया के दौरान तबादले नहीं किये जाते, जो किये भी जाते हैं वे सीधे चुनाव आयोग के आदेश पर किये जाते हैं। ऐसा भी तभी होता है जब कोई अधिकारी चुनाव प्रक्रिया में किसी गड़बड झाले का दोषी पाया जाय। अतुल को पृथला विधान सभा क्षेत्र के गांव असावटी के एक बूथ पर हुई धांधली का दोषी पाया गया है। सतही तौर पर देखने से लगता नहीं कि किसी एक बूथ पर हुई गड़बड़ एवं धांधली के लिये इतने बड़े अधिकारी को दोषी कैसे ठहराया जा सकता है। इसके लिये तो बूथ पर तैनात अधिकारियों तक को ही जिम्मेदार ठहरा कर काम चलाया जा सकता है। ऐसा ही होना था यदि पूर्व उपायुक्त भाजपा सरकार की अंधभक्ति में न पड़ कर, धांधली की रिपोर्ट मिलते ही तुरंत बूथ अधिकारियों पर उचित कार्यवाही कर देते। परन्तु उन्होंने ऐसा करने की अपेक्षा मामले को दबाकर सत्तारूढ दल के प्रति वफ़ादारी साबित करनी चाही थी।

विदित है कि असावटी गांव के एक बूथ पर भाजपा के पोलिंग एजेंट ने अपनी सीट से उठ कर कई बार महिलाओं का वोट खुद अपने हाथों से डाला था। शिकायतें ऊपर तक पहुंची। उपायुक्त ने उचित कार्यवाही करने की बजाय, बूथ पर किसी भी धांधली के होने से ही इन्कार कर दिया। लेकिन धांधली के पूरे धरना क्रम का वीडियो वायरल होने व टीवी चैनलों पर वोटर महिलाओं के बयान आने के बाद सरकार एवं उसके चुनाव आयोग द्वारा अपने वफ़ादार अंध-भक्त को बचाना असंभव हो गया।

यह रहस्य भी किसी से छिपा नहीं है कि चुनाव प्रक्रिया शुरू होने से पहले हर सरकार अपनी पसंद के उन अधिकारियों को महत्वपूर्ण पदों पर, जो कि मलाईदार भी होते हैं, तैनात करती है जो चुनाव प्रक्रिया से जुड़े होते हैं। अपनी पसंद के इन अधिकारियों से हर सरकार यह अपेक्षा करती है कि ये अधिकारी चुनाव जीतने में उनकी मदद करेंगे। बस ऐसी ही एक 'मदद' करने का शिकार उपायुक्त अतुल द्विवेदी जी हो गये।

अदालती फटकार एवं सज़ा के बाद ही अधिकारियों के कान पर जूं रेंगती है

नगर निगमायुक्त ने 50 लाख का जुर्माना भरा, 4 ठेकेदारी कर्मचारी बर्खास्त

फ़रीदाबाद (म.मो.) नगर निगम की हरामखोरी व रिश्वतखोरी के चलते सेक्टर 48 में सीवेज भराव से तंग आये लोग़ों ने एनजीटी में याचिका डाली थी। यह याचिका भी तब डाली थी जब तमाम अधिकारियों व राजनेताओं ने लोग़ों की फ़रियाद अनसुनी कर दी थी। एनजीटी द्वारा सुनवाई करने के बाद नगर निगम पर 50 लाख का जुर्माना लगा, जिसकी वसूली दिनांक 16 मई को कर ली गयी। जुर्माना लगने के बाद निगमायुक्त अनीता यादव ने तुरंत उन चार कनिष्ठ इन्जीनियरों (जेई) को नौकरी से निकाल दिया जो ठेकेदारी पर काम कर रहे थे। निगम की पक्की नौकरी पर लगे किसी एसडीओ, एक्सीयन, एसई या चीफ़ इन्जीनियर को छूने की हिम्मत निगमायुक्त की नहीं थी। छूना तो क्या इनका तो तबादला करने भर से ही सरकार हिल जाती है। ले-दे कर ठेकेदारी में काम करने वाले निरीह कर्मचारियों पर ही निगमायुक्त का डंडा चल सकता है।

सवाल यह भी पैदा होता है कि इस सीवेज भराव के लिये उक्त 4 जेई ही कैसे जिम्मेवार ठहराये गये ? क्या उन्होंने स्वतंत्र रूप से उस सीवर लाइन का निर्माण किया था या वे ही उस लाइन को स्वतंत्र रूप से चलाते थे ? जेई तो हमेशा एसडीओ के आधीन व एसडीओ अपने एक्सीयन के आधीन और उसके दिशा निर्देशन पर काम करते हैं। एक्सीयन अपने अधीनस्थों को ठीक ढंग से निर्देश देकर सही क्रियान्वयन कराता है या नहीं, इसे देखने के लिय एसई व चीफ़ बैठा रखे हैं।

निगमायुक्त द्वारा 4 जेई को बर्खास्त करना स्वत: सिद्ध करता है कि असल काम का क्रियान्वयनव्यम तो केवल ठेके के स्थाई कर्मचारी ही करते हैं जो कि न तो बहुत कम्पीटेंट होते हैं और न ही पूरे पढे-लिखे। इसके अलावा अधिकतर सिफ़ारिशी होते हैं। इनके ऊपर बैठे अधिकारी भी कोई ज़्यादा कम्पीटेंट नहीं हैं परंतु उनकी नौकरी पक्की होने के चलते उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। दरअसल इन्जीनियरिंग के नाम पर इनका काम केवल टेंडर की फ़ाइलें व बिल पास करके ठेकेदार से कमीशन लेने तक ही सीमित रहता है बाकी काम तो ठेकेदार को ही करना होता है।

इन सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह भी है कि निगमायुक्त ने यह कार्यवाही एनजीटी द्वारा जुर्माना ठोके जाने के बाद ही क्यों की, पहले क्यों नहीं की ? उक्त 4 जेई के अलावा उन्होंने करीब 38 मौजूदा एवं पूर्ण इन्जीनियरों को भी कारण बताओ नोटिस जारी किये हैं। ऐसे नोटिसों की न तो कभी इन लोग़ों ने परवाह की है और न ही करेंगे।